(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले थे;

(ग) क्या उक्त योजनावधि के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारी उपाय किए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992—97) के दौरान सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कोई मध्यावधि समीक्षा नहीं की है। तथापि, पूर्व की सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें 1775 चिह्नित ब्लाकों को "कवर" किया गया था, का मूल्यांकन योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने किया था। मूल्यांकन से पता चला था कि यह स्कीम सामान्यतया समस्त क्षेत्रों और राज्यों की आबादी के कमजोर वर्गों के लिए लाभकारी थी। इस अध्ययन में स्कीम की कुछ त्रुटियों और बाधाओं का भी उल्लेख किया गया था।

सभी क्षेत्रों में गरीबों पर केन्द्रित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जून, 1997 से लागू करने से सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली निरर्थक हो गई थी;

(ग) से (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। तथापि, अतिरिक्त उचित दर दुकाने खोलने, अतिरिक्त राशन कार्ड जारी करने और अतिरिक्त गोदाम क्षमता सृजित करने/किराये पर लेने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लक्ष्यों का प्रस्ताव किया गया था। उस समय राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार सामान्यतया लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए थे।

Mass-Movement to Spread Education

*69. SHRIMATI VEENA VERMA: SHRI AKHILESH DAS:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether in view of the fact that even after 50 years of Independence, half of India's population is still illiterate, Government have decided to launch a mass-movement to spread education in the country;

(b) whether any comprehensive action-plan has been or is being worked out; if so, the details in this regard; and

(c) what literacy targets are proposed to be achieved before the country marches into the 21st century?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (c) Government has made continous efforts to achieve the goal of adult literacy since Independence. Launched in 1988, the National Literacy Mission has sought to import functional literacy to 10 crore adults in the 15—35 years age group through Total Literacy Campaigns which are implemented as a mass movement involving all segments of society. Total Literacy Campaigns have covered 7.25 crore adults in 450 districts so far. According to the National Sample Survey Organisation which has recently released the figures of the 53rd round, the literacy rate in the country at the end of 1997 was 62%. The National Agenda for Government states that Government is committed to eradication of illiteracy. Efforts in this direction are being intensified with a focus on women's literacy and greater involvement of Panchayati Raj Institutions.

The Government is also firmly committed to the goal of universalisation of elementary education within a given time-frame. Energetic actions have been initiated to achieve this task through a mission mode and through complementarity of actions between the governmental and non-governmental sectors at various levels. This is a continuing exercise with a new thrust.

Expansion of Railway Network

*70. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state: